10 मार्च तिब्बती जनक्रान्ति के 60वीं वर्षगांठ पर तिब्बती संसद के अभिभाषण।

तिब्बती जनता द्वारा चीन के शासकों के प्रति अहिंसक जनक्रान्ति के साठ वर्ष के उपलक्ष्य में 10 मार्च 2019 यह एक विशिष्ट दिवस के रूप में माना जाता है।

01 अक्टूबर 1949 के दिन चीनी साम्यवादी शासकों ने चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की। इसके उपरान्त उन्होंने तिब्बत को मुक्ति दिलाने के दिखावे पर तिब्बत के भीतर अतिक्रमण करते हुये समस्त तिब्बत को अपने आधीन में कर लिये। इस घटना से अगले नौ वर्ष तक तिब्बती सरकार और परम पावन चौदाहवें दलाई लामा जी ने चीन के साम्यवादी शासन के साथ इस समस्या के हल के लिये हर सम्भव प्रयास किये। जब कि दूसरी तरफ परम पावन और तिब्बती सरकार के बिना किसी जानकारी के चीनी शासकों ने यहाँ तक कि ङापोद् नावाङ् जिगमे की अध्यक्षता वाले तिब्बती सरकार की शान्ति वार्ता प्रतिनिधि मण्डल पर असंवैधानिक तरीके से बलपूर्वक सत्रह सूत्रीय समझौते पर 23 मई 1951 को हस्ताक्षरित किये गये। सत्रह सूत्रीय समझौता की अपेक्षित उपदेश के अनुकूल तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा चीन सरकार के साथ वार्ता सफल होने पर अधिकाधिक प्रयास विफल रहा क्योंकि यह समझौता केवल चीनी साम्यवादी शासन के हितों को सर्वोपरि रखा गया था। यहाँ तक कि तिब्बती सरकार को सार्वजानिक स्तर पर इस समझौता को समर्थन करने का निर्देश जारी किया गया, जिसके फलस्वरूप तिब्बती शान्ति वार्ता प्रतिनिधि मण्डल को 24 से 26 सितम्बर 1951 में तथाकथित सत्रह सूत्रीय समझौता को जारी किया गया।

इस सन्धि के प्राराम्भिक चरण में तिब्बती सरकार के द्वारा तीन शर्त रखे गये थे जिस पर चीनी साम्यवादी शासन यदि अमल करते हैं तब तिब्बती सरकार इस सत्रह सूत्रीय समझौते के लिये बाध्य रहेगा। इस पर चीनी के ओर से समस्त तिब्बती भूभाग को एकीकृत करने हेतु स्हिठोन,